भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 52

जिसका उत्तर सोमवार, 1 दिसम्बर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकीकरण

52. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री मुरारी लाल मीना:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की परिचालन दक्षता, वित्तीय स्थिरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उन्हें और अधिक एकीकृत करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो एकीकरण योजना और तत्संबंधी अपेक्षित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य में कार्यरत किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के उक्त प्रस्तावित एकीकरण से प्रभावित होने की संभावना है और यदि हां, तो बैंकों, उनकी शाखाओं और उन जिलों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्य में, विशेषकर अर्ध-शहरी और ग्रामीण जिलों में ग्राहकों, कर्मचारियों और ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं पर बैंकों के प्रस्तावित विलय के संभावित प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त प्रस्तावित एकीकरण से राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े या दूरदराज के क्षेत्रों में कार्यबल में कमी या शाखाएं बंद होने की संभावना है और यदि हां, तो रोजगार और बैंकिंग सेवाओं तक सार्वजनिक पहुंच पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय अथवा एकीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*****